मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ग) डा०डी०एस० कोठारी की अध्यक्षता वाले शिक्षा आयोग, 1964–66, ने कहा कि देश में कुल शैक्षिक व्यय को 1985–86 तक बढ़ाकर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 6 प्रतिशत तक किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि यह बात सुनिश्चित की जानी चाहिये कि आठवीं पंचवर्षीय योजना से आगे शिक्षा संबंधी परिव्यय समान रूप से राष्ट्रीय आय के 6 प्रतिशत से अधिक रहेगा।

वर्ष 1991–92 के व्यय संबंधी ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। केन्द्र तथा राज्यों में शिक्षा विभागों का राजस्व बजट वर्ष 1990–92 के कुल राजस्व बजट के 12% तक आंका गया है।

Indian history Congress

3398. KUMARI ALIA:
SHRIMATI BASANTI SARMA:
SHRI KAPIL VERMA:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention have been invited to the news item which appeared in the 'Indian Express', New Delhi dated 30th November, 1991 under the caption "Fresh controversy dogs history Congress";

(b) if so, Government's reaction thereto;

(c) the amount of grant given annually to the Indian History Congress (IHC) in the last three years and the purpose for which it is given;

(d) what type of administrative, financial and other control is exercised by Government over the affairs of the Indian History Congress; and

(e) what are the important projects assigned by Government to the Indian History Congress during the last three years and achievements made by the Indian History Congress therein?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) to (e) Yes, Sir. The Indian History Congress is a voluntary organisation of historians which manage its own affairs. Government do not exercise any control over it. According to information furnished by the Indian Council of Historical Research, the Council, under its Grant-in-Aid Scheme, gave the Indian History Congress grant of Rs. 80,000 each year for publishing the proceedings of the Congress, holding the symposium and meeting incidental expenses during 1990-91 and 1991-92. Prior to 1990-91, the amount of grant to the Congress was Rs. 25,000 for proceedings and Rs. 10,000 for symposium per annum. The University Grants Commission has also agreed, in principle, to contribute a token sum of Rs. 10,000 in 1991 to the Congress. Government has, as a special case, provided grant of Rs. 3.00 lakhs to I.H.C. to hold its 1991 Congress. According to the information furnished by Indian Council of Historical Research, the Council neither provides any grant for meeting expenditure on the Secretariat of the Congress nor has it approved any projects of the Indian History Congress for the last 3 years.

दिल्ली में साक्षरता कार्यक्रम

3399. श्रीमती बसन्ती शर्मा
श्री कपिल वर्मा:
श्रीमती वीणा वर्मा:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के साथ-साथ साक्षरता कार्यक्रम चला रहा है; यदि हां, तो यह कार्यक्रम कब से चलाया जा रहा है और इसके क्या उद्देश्य हैं;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इस कार्यक्रम के लिये बजट में कितना आवंटन किया गया; और

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने यह सिफारिश की थी कि स्वैच्छिक संस्थाओं को इस कार्यक्रम से सहबद्ध किया जाना चाहिए, यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) जी हां । साक्षरता, प्रौढ़ शिक्षा के चार संघटकों में से एक है, जो संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में 2 अक्तूबर, 1978 से लागू है । परिणात्मक तौर पर, कार्यक्रम का उद्देश्य वरीयता के तौर पर 15-35 आयु वर्ग के सभी प्रौढ़ निरक्षरों को साक्षर बनाना है । गुणावत्तात्मक रूप में, कार्यक्रम का उद्देश्य, शिक्षुओं को साक्षरता व अंक ज्ञान में आत्मनिर्भर बनाना, अधिकारों से वंचित रहने के कारणों एवं विकास की प्रक्रिया में उनकी सहभागिता के प्रति उनको जागरूक करना, उनके आर्थिक स्तर एवं ग्राम दशा को सुधारने के लिए दक्षता प्रदान करने की व्यवस्था करना और राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, महिला-समानता और लघु परिवार मानदण्डों आदि जैसे मूल्यों को उनके मन में बिठाना है ।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सरकार के अधीन विभिन्न योजनाओं के लिए केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को 365.57 लाख रुपए की धनराशि संस्वीकृत और जारी कर दी गई है । इसके अतिरिक्त, संघ शासित प्रशासन द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली प्रौढ़ शिक्षा की कई योजनाओं के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान योजनागत 164.00 लाख रुपए और योजनेतर 243.32 लाख रुपए का प्रावधान था ।

(ग) स्वैच्छिक एजेंसियों की सहायता योजना को परिशोधित एवं पुनर्गठित किया गया है । मार्ग-निर्देशों के साथ-साथ परिशोधित योजना को संघ शासित क्षेत्र दिल्ली सहित सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में परिचालित कर दिया गया है । परिशोधित योजना और मार्ग-निर्देशों के प्रत्युत्तर में अभी प्रस्ताव प्राप्त किए जाने हैं ।

Activities of CARE Incorporated

3400. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) wheter it is a fact that the activities of the American Agency, CARE Incorporated,, are limited to feeding programmes in school; and

(b) whether Government propose to review/regulate the activities of CARE?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS) WITH ADDITIONAL CHARGE OF MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT) (KUMARI MAMATA BANERJEE): (a) No, Sir. In addition to feeding programmes in school. CARE—India provides food commodities for supplementary feeding to children below 6 years, expectant and nursing mothers under Integrated Child Development Services Programme. CARE India also provides assistance to some non-food programmes aimed at increasing the income and improving the nutritional levels of families covered under ICDS programme.

(b) The programme of CARE India are governed by Indo-CARE agreement 1950. Every year CARE-India submits their annual action plan called list of provisions for the approval of Government of India.

Introduction of self Finance Scheme at Higher Educational level

3401. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRI SOM PAL:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the wide spread evil of donation for admission in technical institutions prevailing